महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष-7 | अंक-1 | मुंबई, 1 से 15 फरवरी 2019 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

महाराष्ट्र को मिला सूखा राहत पैकेज

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र को मिला सूखा राहत पैकेज सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार ने 4,714.28 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है। हालांकि यह राहत पैकेज उम्मीद से काफी कम है। सूखे की विकराल स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के पास 7,900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखा अकाल का रूप धारण करता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से लगाई जा रही है कि इन इलाकों में जानवरों के लिए चारा और पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्थिति से निपटने में राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हालत सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारा शिविर शुरू किया है। राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए अपने कोष से करीब 2,900 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर चुकी है और केंद्र सरकार से 7,900 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराष्ट्र के लिए सूखे से निपटने के लिए 4714.28 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 7,214.03 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि मंजूरी की गई है। यह राशि केंद्रीय राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को दी जाएगी। महाराष्ट्र के अलावा पांच और राज्यों व एक केंद्र शासित राज्य के लिए भी केंद्रीय राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस राहत पैकेज का फायदा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पुदुच्चेरी के किसानों को मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्राथमिक तौर पर राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए अपने कोष से करीब 2,900 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर चुकी है और केंद्र सरकार से 7,900 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराष्ट्र के लिए सूखे से निपटने के लिए 4714.28 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी गई।

चालू रबी सत्र में गेहूं की होगी बंपर पैदावार

10 करोड़ टन के पार जा सकता है गेहूं उत्पादन

नई दिल्ली (विसं)। चालू रबी सत्र में देश में गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन से ज्यादा हो सकता है। पहली बार उत्पादन इस स्तर पर पहुंचेगा। गेहूं का फरवरी वायदा भाव मामूली गिरावट के साथ 2018 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। इससे पहले नवंबर में गेहूं का भाव 2100 रुपये के प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया था। मौसम की मौजूदा स्थितियों और बंपर फसल की उम्मीद के कारण गेहूं की कीमतें वायदा और हाजिर बाजार में नीचे आई हैं। आगे भी कीमतों में गिरावट दिख सकती है, क्योंकि फरवरी के आखिर तक नई फसल की आवक शुरू हो जायेगी। गेहूं का फरवरी वायदा भाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर दिखा सकता है।

पिछले एक महीने में गेहूं का भाव करीब 3-4 फीसदी लुढ़का है, क्योंकि सरकार के पास गेहूं का काफी स्टॉक है। इसके अलावा रबी सीजन में गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर को छू सकती है। इसे देखते हुए आगे भी कीमतों पर दबाव दिख सकता है। गेहूं फरवरी वायदा में मौजूदा स्तर के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। एक हफ्ते में भाव 1970-1980 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर दिख सकता है। गेहूं की फसल के लिए बढ़िया है बेमौसम बारिश करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस त्यागी के मुताबिक, जिन इलाकों में अभी गेहूं की फसल में बालियां नहीं आयी हैं, उनमें ओला या बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये फायदेमंद है। इससे गेहूं की बालियों का आकार भी बढ़ेगा। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 10 करोड़ टन के पार जा सकता है उत्पादन हाल ही में कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने कहा था कि राज्य सरकारों से मिल रही सूचनाओं के आधार पर गेहूं की पैदावार 10 करोड़ टन के स्तर को पार कर जाने की उम्मीद है। मल्होत्रा ने कहा कि देश में मौसम की स्थिति प्रमुख रबी फसल, गेहूं के लिए अनुकूल रही है। केंद्र जल्द ही वर्ष 2018-19 की रबी फसलों के लिए उत्पादन का अनुमान जारी करेगा। अब तक गेहूं की खेती का रकबा 296 लाख हेक्टेयर है। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 8 लाख हेक्टेयर कम है लेकिन इस कमी के बावजूद गेहूं की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। चालू रबी सीजन के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 1,735 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,840 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।

पंजाब में कर्ज माफी के तीसरे चरण की शुरुआत

जालंधर (विसं)। पंजाब में किसान फसल ऋण माफी योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इस चरण के तहत राज्य सरकार ने लुधियाना के 7,778 किसानों के 64.44 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं। लुधियाना से सांसद सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने इस संबंध में ऋण मोचन प्रमाणपत्र किसानों के बीच वितरित किया। बिट्टू ने कहा कि इस योजना के तीसरे चरण के तहत गिल क्षेत्र के 861 किसानों पर बकाया 6.22 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दाखा क्षेत्र के 993 किसानों के 7.72 करोड़ रुपये कर्ज भी माफ किए गए हैं। बिट्टू ने कहा कि इसी तरह, दूसरे क्षेत्रों के किसानों के ऋण भी माफ हुए हैं। ऋण माफी से जुड़े प्रमाणपत्र किसानों के बीच वितरित किए गए। बिट्टू ने कहा कि पिछले दो चरणों में लुधियाना के ही 38,432 किसानों के 311.71 करोड़ रुपये के कृषि ऋण पहले ही माफ किए जा चुके हैं और इस संबंध में उन्हें प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके चुके हैं।

करंजा बंदरगाह से मिलेगा मत्स्य उद्योग को बढ़ावा

मुंबई (कासं)। देश में मत्स्य उत्पादन और निर्यात को गति देने के मकसद से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करंजा मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है इससे राज्य का मत्स्य उत्पादन 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन देशों का विकास हुआ है वह समुद्र के रास्ते से ही हुआ है।

किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6680 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर

नई दिल्ली (विसं)। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है। इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा। इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में किसान सूखे से पीड़ित थे और सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण लिए सरकार खासतौर से कोशिश कर रही है। कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है।

पिछले महीने केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था, और उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों को और भी राहत दी जाएगी।

देश के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा जल्द, और इंतजार की जरूरत नहीं: कृषि राज्य मंत्री: साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी बदलाव किया जा सकता है। स्मॉल और मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए जा सकते हैं। उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के लाभ के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार की प्लानिंग है कि उन किसानों के भी नुकसान की भरपाई हो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है। इसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा. नीति आयोग की तरफ से भी इसमें बदलाव की सिफारिश की गई है। कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा था कि जल्द ही देश के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने राजधानी में नेशनल कांफ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको (पैकेज के लिए) अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

सम्पादकीय

किसान को कर्जमाफी नहीं लाभकारी मूल्य मिले

कांग्रेस की तीन राज्यों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई हालिया चुनावी जीत में किसानों की कर्जमाफी के वायदे को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब कांग्रेस ने इसे 2019 के आम चुनावों में भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की कर्जमाफी की मांग को तो खारिज कर दिया है, परंतु किसानों को एक राहत पैकेज देने की बात जरूर चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में देश का किसान कई बार कर्जमाफी और फसलों के लाभकारी मूल्य को लेकर आंदोलन कर चुका है। जब भी किसानों का कर्जा माफ करने या उन्हें राहत पैकेज देने की बात आती है तो देश में हाहाकार मच जाता है। अर्थशास्त्री इसके कारण देश का राजकोषीय घाटा बढ़ने और ऋण अनुशासन खराब होने की चेतावनी देने लगते हैं। किसानों की कर्जमाफी या राहत पैकेज को राजनीतिक से अलग सरकारी आर्थिक नीतियों के परिपेक्ष्य में देखने की भी आवश्यकता है। पिछले 70 वर्षों में सरकारों ने उपभोक्ता हित में महंगाई दर को काबू करने की नीतियों का अनुसरण किया है, जिस कारण उन्होंने फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में अनुपातिक वृद्धि कभी नहीं की। इसी प्रकार सरकारें किसानों के प्रतिकूल व्यापार नीतियां अपनाती रही हैं ताकि आम नागरिकों को सस्ता खाद्यान्न मिलता रहे और महंगाई दर काबू में रहे। ओईसीडी के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2000-2017 के बीच विभिन्न सरकारी नीतियों के हस्तक्षेप के कारण किसानों की आमदनी औसतन 14 प्रतिशत घटी है। तमाम नीतियों के बावजूद देश के अधिकांश नागरिक अब भी बाजार से महंगे फल, सब्जियां और अनाज खरीदते हैं, परंतु उस पैसे का बहुत कम हिस्सा ही किसानों तक पहुंच पाता है। इसका कारण सरकारों द्वारा बिचौलियों को काबू नहीं कर पाना और पर्याप्त भंडारण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संरचना खड़ी नहीं कर पाना है। आज भी एक तरफ करीब एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के फल, सब्जी, अनाज सड़ जाते हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में केवल सात प्रतिशत खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि चीन में 33 प्रतिशत और अमेरिका में 65 प्रतिशत! एक तरफ हम अपने किसानों को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने में विफल रहे हैं तो दूसरी तरफ खेती की लागत भी लगातार बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप खेती घाटे का सौदा बन गई और किसान कर्ज के जाल में फंसता चला गया। किसान की ऋण माफी की मांग उसे उचित मूल्य नहीं देने से जुड़ी हुई है। सरकार ने किसानों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित 'संपूर्ण लागत-सी 2' का डेढ़ गुना मूल्य देने का वायदा किया था, परंतु इसे आज तक पूरा नहीं किया गया। कम से कम आकलन भी किया जाए तो भी, लागत का डेढ़ गुना मूल्य नहीं मिलने और अन्य सरकारी नीतियों के चलते पिछले साढ़े चार वर्षों में ही लगभग नौ लाख करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हुआ है और किसान कर्ज में डूब गए हैं। इसी रकम को किसान कर्जमाफी के रूप में मांग रहे हैं जो उनको पहले ही मिल जानी चाहिए थी। अतः इसे कर्जमाफी नहीं, बल्कि पुराने बकाये का भुगतान कहना ज्यादा उचित होगा, यह किसान का हक है। देश का खजाना किसानों पर लुटाए जाने का आरोप लगाने वाले अर्थशास्त्री अन्य सरकारी नीतियों पर कोई चर्चा नहीं करते। आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा यूपीए के दस वर्षों के शासनकाल में लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपये और इस सरकार के चार वर्षों के शासनकाल में लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया। यानी पिछले 15 सालों में ही कुल मिलाकर 5.70 लाख करोड़ रुपये की राहत मिली है-जिसका लाभ मुख्यतः धन्ना सेठों ने ही उठाया है। बट्टे खाते यानी राइट ऑफ की बहुत कम रिकवरी होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसके मुकाबले केंद्र सरकार ने किसानों को 2008 में लगभग 72,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की राहत दी थी, परंतु सीएजी की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार इस पर वास्तव में लगभग 52,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। इस दौरान किसानों को कुछ राज्य सरकारों ने भी राहत दी है, परंतु यदि उद्योगों को दी गई सब्सिडी और टैक्स छूट जोड़ दें तो किसानों की कर्जमाफी का आंकड़ा नगण्य है। देश में राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जिसका लाभ मुख्यतः संपन्न तबका उठाता है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों आदि को दी जाने वाली सब्सिडी और रियायतें भी देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जिसे 'रेवेन्यू फोरगोन' नाम से बजट में दर्ज किया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते केंद्र और राज्य सरकारों पर दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक बोझ पड़ने का अनुमान है। इन सब पर न तो कभी हाहाकार मचता है, ना ही किसान कभी आपत्ति करते हैं। इन सबके मुकाबले हम किसानों को सहायता तो बहुत कम दे रहे हैं, परंतु शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों ने कुल मिलाकर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये की किसानों की कर्जमाफी की घोषणाएं की हैं, पर क्या ये धरातल पर पूर्ण हुई हैं। उत्तर प्रदेश में घोषित 36,359 करोड़ रुपये की कर्जमाफी के सापेक्ष अभी तक लगभग 25,000 करोड़ रुपये की ही कर्जमाफी हुई है। पंजाब में घोषित 10,000 करोड़ रुपये के सापेक्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में 34,000 करोड़ रुपये की घोषणा के सापेक्ष लगभग 17,000 करोड़ रुपये ही माफ किए गए हैं। कर्नाटक में घोषित 34,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की तो अभी शुरुआत ही हुई है, वहां कितनी राशि माफ होगी यह तो भविष्य ही बताएगा। अतः कर्जमाफी की बड़ी-बड़ी घोषणाओं और वास्तविक माफी में भी काफी बड़ा अंतर है।

पपीते की उन्नत किस्म व नर्सरी तैयार करने की विधि

भारत का विश्व के पपीता उत्पादक देशों में प्रथम स्थान है। इसके औषधीय गुणों एवं आर्थिक रूप से लाभकारी होने के कारण पूर्व के कुछ वर्षों में लोगों ने इसकी खेती और अधिक ध्यान देना शुरू किया जिससे पिछले एक दशक में पपीता के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई। इसके फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आम के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी एवं खनिज लवण भी पाये जाते हैं। कच्चे फल का उपयोग पेठा, बर्फी, खीर, रायता इत्यादि के लिए किया जाता है, जबकि पके फलों से जैम, जेली, नेक्टर तथा कैन्डी, आदि बनाये जाते हैं।

पपीते की उन्नत किस्म

पपीते की इन किस्मों की बुवाई कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है-

पूसा नन्हा - यह एक अत्यंत बौनी किस्म है जिसमें 15-20 सेमी जमीन की सतह से ऊपर फल लगना प्रारंभ हो जाता है। इस किस्म के फल मध्यम भार के व अण्डाकार होते हैं। यह डायोशियस प्रकार की किस्म है, जो 3 वर्षों तक फल दे सकती है।

सनराइज़ सोलो - सनराइज सोलो किस्म एक उन्नत अधिक उपज देने वाली चयनित किस्म है। इस किस्म के फल का गूदा लाल-नारंगी रंग का होता है। फल मध्यम आकार का होता है, जिसका वजन 425 से 620 ग्राम प्रति फल होता है।

वाशिंगटन - इस किस्म का पौधा अच्छी बढ़वार वाला होता है। यह महाराष्ट्र की प्रसिद्ध किस्म है, जिसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है, कि इसके पौधे के कुछ भाग बैंगनी रंग के होते हैं। केवल फल तथा पत्तियां ही हरी होती हैं। यह पपेन उत्पादन के लिए प्रचलित किस्म है। इसके फल अण्डाकार, मीठे, स्वादिष्ट एवं सुगंधित होते हैं। फल का औसत वजन 1.0 से 1.5 किलोग्राम होता है। फल का गूदा पीले-लाल रंग का होता है तथा इसमें कुछ ही बीज होते हैं। फल की भण्डारण क्षमता अधिक होती है।

को.7 -यह गाइनोडाशियस किस्म है जो वर्ष 1997 में विकसित संकर किस्म है। यह किस्म 100-110 फल प्रति पौध उपज देती है। इसके फल लंबे अण्डाकार होते हैं एवं गूदा लाल रंग का होता है।

रेड लेडी 786 - यह प्रजाति अधिक उत्पादन व रोगों से लड़ने की क्षमता वाली एवं उभयलिंगी होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। गूदा लाल रंग का व छिलका मोटा होता है।

विनायक - यह प्रजाति मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त व 8-10 माह में फलन प्रारंभ हो जाता है। फलों का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तथा आकार गोल व बेलनाकार होता है।

पूसा (डेलीसियस, मेजस्टी, ड्वार्फ, जाइंट), सोलो, हनीड्यू, सिलोन, कोयम्बटूर आदि भी उन्नत प्रजातियाँ हैं।

बीज

1. बीज पूर्ण पका हुआ हुआ हो, अच्छी तरह सूखा एवं शीशे की बोतल या जार में रखा हो, जिसका मुंह ढका हो और 6 महीने से अधिक पुराना न हो, उपयुक्त है।
2. बीज किसी विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए।
3. एक हैक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु 500 ग्राम बीज उपयुक्त होता है।

बीजोपचार

पपीते के बीज को बोने से पहले कैप्टन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 3 ग्राम कैप्टन एक किलो बीज को उपचारित करने के लिए काफी है।

पपीते की नर्सरी के लिए स्थान का चयन

- ❖स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए, जहां से पानी निकाल उचित हो।
- ❖भूमि दोमट बलुई होनी चाहिए जिसका पीएच मान लगभग 6.5 हो।
- ❖स्थान, पानी स्रोत के समीप होना चाहिए।
- ❖स्थान देख-रेख की दृष्टि से भी निकट होना चाहिए।
- ❖स्थान, खेत के किनारे पर होना चाहिए ताकि कृषि कार्यों में रुकावट न आए।
- ❖कंकड़-पत्थर से रहित हो।
- ❖वह स्थान जहां पर तेज धूप तथा अधिक छाया ना आये, चुनना चाहिए।

नर्सरी की तैयारी

नर्सरी हेतु तैयार भूमि को अच्छी प्रकार जुताई-गुड़ाई करके समस्त कंकड़, पत्थर और खरपतवार निकाल कर साफ कर देना चाहिए। तथा जमीन को 2 प्रतिशत फॉर्मलीन से उपचारित कर लेना चाहिए।

बुवाई-विधि

भूमि की सतह से 15 से 20 सेमी उठी हुई संकरी क्यारियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 सेमी तथा बीज से बीज की दूरी 3 से 4 सेमी रखते हैं। बीज को 1 से 3 सेमी से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए।

प्लास्टिक थैलियों में बीज उगाना

पौधों को पॉलीथीन की थैलियों में उगाने हेतु छेद किये गये 150 से 200 गेज वाले पॉलिथिन के थैलों, जिनकी लंबाई 15 सेमी तथा चौड़ाई 12 सेमी हो काम में लाया जा सकता है। थैलों को एक तिहाई बालू, एक तिहाई कम्पोस्ट तथा एक तिहाई मिट्टी मिलाकर भर लेना चाहिए। इसके अलावा थैलों को दो शग कोकोपिट, 1 शग वर्मीकुलाइट तथा 1 शग परलाइट के मिश्रण से भी कर सकते हैं। प्रति थैले में 1-2 बीज एक सेमी की गहराई पर बोने के बाद पानी से सिंचाई कर देना चाहिए।

नर्सरी की देखभाल

- ❖बोई गई क्यारियों को सूखी घास या पुआल से ढक दें। नर्सरी में पानी का हल्का छिड़काव हजारे द्वारा सुबह के समय करना चाहिए। खराब मौसम से बचाने के लिए पुआल या पॉलिथीन से ढकना आवश्यक होता है।
- ❖कीड़ो से नर्सरी को बचाने के लिए 0.2 प्रतिशत किसी कीटनाशक (फॉलीडाल धूल 5 प्रतिशत) का बुरकाव करना चाहिए।
- ❖नर्सरी में गलन रोग दिखाई पड़े तो मैंकोजेब या रिडोमिल या कॉपर ऑक्सिक्लोराइड (2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर तुरंत छिड़काव करना चाहिए।
- ❖क्यारी में उगे हुए पौधों में जब 2-3 पत्तियाँ आ जाएँ तो क्यारी से पॉलिथीन बैग में स्थानांतरण करना चाहिए। यदि पौधे पॉलिथीन बैग में है और एक से अधिक पौधे तो उन्हें भी अलग बैग में स्थानांतरित कर देते हैं जिससे एक ही स्थान पर सघन ना होने पायें।

फरवरी में बोनी वाली फसल : उड़द की खेती

किसान भाइयों, फरवरी माह में बोये जाने वाली फसल उड़द की खेती की जानकारी कैसे की जाती है और कैसे इसका लाभ लिया जाता है। आइये जानते है इस बारें में:-

कुल- लेग्यूमिनोसी

वानस्पतिक नाम - विग्ना मुंगो

महत्व : उड़द की फसल एक दलहनी फसल है तथा इसके दाने में लगभग 25 प्रतिशत प्रोटीन, 60प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 11 प्रतिशत वसा तथा शेष अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्द की दाल, इमरती, इडली, डोसा, आदि व्यंजनों के रूप में खाया जाता है। पशुओं को इसके दाने का छिलका तथा भूसा खिलाया जाता है।

उत्पत्ति : बैवीलोन के अनुसार उड़द का जन्म स्थान भारतवर्ष है।

उत्पादन केंद्र : यह संसार के बहुत से देशों में उत्पन्न किया जाता है। भारतवर्ष में इसकी खेती मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब कर्नाटक आदि प्रदेशों में की जाती है।

उत्तर प्रदेश में इसकी खेती अधिकतर सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, बदायूं, झांसी, ललितपुर, बाराबंकी, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों में की जाती है।

जलवायु : उर्द की फसल के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश में उड़द की फसल मुख्य रूप से खरीफ की फसल में उगाई जाती है। परंतु आजकल उर्द को जायद की फसल में भी उगाया जाता है। इसकी फसल के उचित वृद्धि के लिए 25एष्ट-30एष्ट का तापमान उपयुक्त रहता है।

भूमि : उर्द की फसल के लिए दोमट भूमि उपयुक्त होती है। वैसे सभी प्रकार की भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है। अम्लीय, क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं होती है। इसकी फसल में वर्षा होने पर खेतों से जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा इसकी फसल अधिक पानी में नष्ट हो जाती है।

उरद की उन्नत प्रजातियां कौन सी हैं।

टाइप-9:यह जायज तथा खरीफ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह जल्दी पकने वाली जाति है जो खरीफ की फसल में 90 से 95 दिन में तथा जायद की फसल में 80 से 85 दिन में पक जाती है। इसकी पैदावार लगभग 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

टाइप-27 : यह खरीफ की फसल में उगाई जाती है। यह लगभग 130 दिन में पक जाती है। इसकी उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

पंत उड़द- 19: इस जाति की उड़द जयद और खरीफ की फसलों में उगाई जाती है। इसकी उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह जाति पीला मौजेक रोग की प्रतिरोधक क्षमता रखती है।

पंत उड़द-30 : इस जाति की उर्द जायद तथा खरीफ की फसल में उगाई जाती है। यह 80 से 90 दिन में पक जाती है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें पीला मौजेक रोग की प्रतिरोधक क्षमता होती है।

पूसा-1: इस जाति की उड़द जायद तथा खरीफ की फसल में उगाई जाती है। यह लगभग 85 दिन में पक जाती है। इसके उपज 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।

खेत की तैयारी कैसे की जाती है?

उर्द की फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार करते समय पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से लगभग 15 सेमी गहरी करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 जुताई देशी हल तथा हैरो से करके मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए और खेत को समतल करने के लिए खेत में पाटा लगा देना चाहिए।

बुवाई का समय : खरीफ की फसल की बुवाई के लिए उड़द की फसल को 20 जून से 15 जुलाई तक बो देना चाहिए तथा जायद की फसल की बुवाई 20 फरवरी से 20 मार्च तक कर देनी चाहिए।

बीज की मात्रा तथा बीजोपचार: उर्द की फसल की बुवाई के लिए बीज की मात्रा इस प्रकार प्रयोग करनी चाहिए।

मात्रा : खरीफ की फसल के लिए 12 से 16 किग्रा/है., तथा जायद की फसल में 22 से 25 किग्रा/है. बीज की मात्रा पर्याप्त होती है।

बीजोपचार : उर्द के बीज को बोने से पूर्व राख डालकर हल्के हाथ से मसलकर बोना चाहिए।

बुवाई की विधि : उर्द की फसल को हल के पीछे कूंडों में बोना चाहिए। खरीफ की फसल में एक कूंड से दूसरे कूंड का अंतर 40-45 सेमी तथा जायद की फसल में 20-25 सेमी रखना चाहिए।

खाद एवं उर्वरक : उर्द की फसल में गोबर की खाद फसल बोने से 1 माह पूर्व जुताई के समय देनी चाहिए जिससे वह मिट्टी में मिल कर अच्छी प्रकार सड़ जाए उड़द की फसल के लिए 20 किग्रा नाइट्रोजन, 45 किग्रा फास्फोरस तथा 3 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। उर्वरकों को फसल की बुवाई के समय बीज की पंक्ति वाले कूंड से 5 सेमी की दूरी पर बीज से 5 सेमी गहराई पर डालना चाहिए।

सिंचाई एवं जल निकास : खरीफ की फसल में अधिकतर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बरसात न हो और फसल मुरझाने लगे तो फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। तथा अधिक वर्षा होने पर खेत से जल की निकासी कर देनी चाहिए तथा जायद की फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।

निराई-गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण : खरपतवारों के नियंत्रण हेतु उर्द की फसल में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद खुरपी से निराई-गुड़ाई कर देनी चाहिए यदि आवश्यक हो तो 15 दिन बाद दूसरी निराई-गुड़ाई भी खुरपी से कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खरपतवार के नियंत्रण हेतु बुवाई के पूर्व 2 किग्रा बेसालीन को 8,000 ली. जल में घोलकर एक हेक्टेयर भूमि पर छिड़ककर हैरो से जुताई कर देनी चाहिए। ऐसा करने से खेत में खरपतवार नहीं उगते।

रोग नियंत्रण : उर्द की फसल में निम्नलिखित रोग लगते हैं-

पीला मौजेक : यह रोग एक वायरस के द्वारा फैलता है। इस वायरस को सफेद मक्खी से एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। इस रोग में पहले पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं और अंत में पत्ती पीली होकर सूख जाती है इस रोग के उपचार हेतु मेटासिस्टॉक्स 0.1 प्रतिशत के घोल का फसल पर कई बार छिड़काव करना चाहिए।

चारकोल विगलन : यह रोग फफूंदी द्वारा उत्पन्न होता है इसमें पौधे की जड़े तथा तना सड़ जाता है। इस रोग से फसल के बचाव हेतु उर्द की फसल को ज्वार, बाजरा जैसी फसलों के साथ मिलाकर उगाना चाहिए तथा बीज को बोने से पहले 0.25 प्रतिशत ब्रेसीकाल से उपचारित करके बोना चाहिए।

एन्थ्रेक्नोज : यह रोग फफूंदी से फैलता है इस रोग के कारण पत्तियों तथा फलियों पर भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ते हैं जो बाद में गहरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग से बचाव हेतु फसल पर डाइथेन एम-45 के 0.25त्न घोल का छिड़काव करना चाहिए।

कीट नियंत्रण : उड़द की फसल में निम्नलिखित कीट हानि पहुंचाते हैं-

कमला (रोयेदार सूंडी) : यह कीट पौधे की सभी पतियों को खा जाता है जिससे पौधा पत्तियों विहीन हो जाता है। इस कीट की रोकथाम हेतु इंडोसल्फान 35 ई. सी. के 2 लीटर को 800 लीटर जल में घोलकर 1 हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करना चाहिए।

सफेद मक्खी : यह पौधों की पत्तियों का रस चूस्ती है। तथा पीला मौजेक रोग के वाइरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाती है। इस कीट की रोकथाम हेतु फसल पर 0.1 प्रतिशत मैटासिस्टाक्स के घोल का छिड़काव करना चाहिए।

हरा तेला : यह कीट पत्तियों का रस चूस लेता है जिससे पत्तियां मुड़ जाती है। तथा पौधा बीमार हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए नुवाक्रान 40 ई.सी. के 0.4 प्रतिशत का घोल फसल पर छिड़कना चाहिए।

कटाई : जब फसल पक जाती है तो इसकी फलियां पूर्ण रूप से काली हो जाती हैं। इस अवस्था में दरांती के द्वारा इसकी कटाई कर ली जाती है। तथा फसल को किसी टाट की गठियां में बांधकर खलियान में एकत्रित कर लेते हैं।

मंडाई : खेत में फसल को कई दिन तक डालकर अच्छी प्रकार सूखा लेते हैं। तथा फिर इस पर बैलों की दायं चलाई जाती है। इसके बाद भूसे को दाने से अलग कर लिया जाता है।

उपज : खरीफ की फसल में उड़द के उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा जायद की फसल में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है।

भंडारण : उड़द के दानों में डोरे पैदा हो जाते हैं। अत: इसका भंडारण करने से पहले इसके दानों को अच्छी प्रकार सुखाकर लोहे की टंकी में रखकर दवाई रखकर वायुरोधी कर देना चाहिए।

विपणन : उड़द की बाजार में बहुत अधिक मांग होती है। अत: किसान अपनी आवश्यकता से अधिक फसल को बाजार में बेच सकते हैं।

भारत का दूसरा कृषि संस्थान स्थापित

नई दिल्ली (विसं)। केंद्रीय कृषि मंत्री, राधा मोहन सिंह ने झारखंड के हजारीबाग शहर के पास गौरीकर्मा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने देश में दूसरे IARI की स्थापना के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की।

कृषि मंत्री ने कहा, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों की सिफारिशों पर तत्काल ध्यान दिया और बिना अधिक देरी के नई दिल्ली के बाद देश के दूसरे आईएआरआई की स्थापना को मंजूरी दी।

सिंह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी घोषणाओं में नहीं बल्कि प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में दूसरे IARI की आधारशिला रखी। IARI परियोजना युवा किसानों और वैज्ञानिकों की किस्मत को बदल देगी क्योंकि उन्हें कृषि विज्ञान में बेहतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 200 करोड़ की लागत से बना यह संस्थान अपने कामकाज से हजारीबाग के सुदूर इलाके में पूरे पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में एक कृषि क्रांति लाएगा. इससे कृषि विकास

की काफी संभावनाएं होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से, हर साल कृषि में 159 वैज्ञानिकों को बेहतर तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा और 90 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। संस्थान में कृषि, पशुपालन और अनुसंधान सहित तीन संकाय भी होंगे. केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और हजारीबाग के नेता जयंत सिन्हा के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई परियोजनाओं ने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों को सर्वांगीण विकास में मदद की है।

किसानों को जोड़ने की एमसीएक्स की कवायद

मुंबई (कासं)। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) कृषि जिंसों के वायदा कारोबार की फिर से वापसी में जुटा है। एक्सचेंज ने सीधे किसानों को जोड़ने के अभियान को तेज किया है। एमसीएक्स की ओर से अब तक 78 किसानों संगठनों (एफपीओ) को एक्सचेंज से जोड़ा जा चुका है। गैर कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में अग्रणी एमसीएक्स किसान जोड़ अभियान ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि एक्सचेंज कृषि जिंसों के वायदा कारोबार को एक बार फिर से प्राथमिकता की सूची में लाने के लिए प्रयासरत है। किसानों से सीधे जुड़ने का फायदा भी एक्सचेंज को हुआ है। चालू महीने में गुजरात के सोमनाथ-गिर जिले के लगभग 1,600 किसानों के समूह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (एफपीओ) ने पहली बार एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर कपास जमा किया है।

एमसीएक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ मृगांक परांजपे कहते हैं कि किसानों के अधिक से अधिक संगठनों को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इन प्रयासों में हम सफल रहे हैं। एमसीएक्स की ओर से अब तक 78 एफपीओ को कमोडिटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। किसानों को कपास के भाव में उतार-चढ़ाव के जोखिम में से मुक्त करके संगठित बाजार के तहत शामिल किया जा रहा है। इसके लिए उचित तंत्र और मंच प्रदान कर किसान संगठनों को एक्सचेंज पर अपने कॉटन के भाव लॉक करने और उनके जोखिमों को कवर करने के लिए समझाया जा रहा है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजनाः रघुवर दास

दुमका (विसं)। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी सरकार कृषि आशीर्वाद योजना प्रारम्भ करने जा रही है दुमका के पुलिस लाइन मैदान पर गणतंत्र दिवस के संबोधन में दास ने कहा कि भ्रष्टाचार एवं उग्रवाद से मुक्त झारखण्ड बनाने का पिछले 4 वर्षों में उनकी सरकार ने प्रयास किया है जिस में उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए हमने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम है कि उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आयी है। सरकार के अच्छे प्रयासों का ही फल है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गयी है तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई है। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार कृषि आशीर्वाद योजना प्रारम्भ करने जा रही है जिसका लाभ राज्य के 22 लाख 76 हजार लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा। राज्य के किसानों को नई एवं उन्नत तकनीकों से अवगत कराने हेतु अब तक राज्य के 76 किसानों को इस्राइल दौरे पर भेजा गया।

पहली बार भैंसदेही में हो रहा है एप्पल बेर का उत्पादन

भैंसदेही (विसं)। आज जहां रासायनिक खाद एवं दवाइयों के सहारे खेती को प्राथमिकता दी जाती है तो वहीं भैंसदेही का एक ऐसा किसान है 12 वर्षों से लगातार जैविक खाद का उपयोग कर गेहूं, चना, तुवर के अलावा अब एपल बेर का बंपर उत्पादन कर रहा है। बैतूल जिले के आदिवासी अंचल का यह किसान गेहूं चना और तुवर के प्रति एकड़ रिकॉर्ड उत्पादन के लिए कृषि विभाग और इससे जुड़ी कई संस्थाओं के प्रशस्ति पत्र पा चुका है और किसानी का जुनून रखने वाला यह कृषक मप्र नहीं महाराष्ट्र में भी अपनी पहचान बना चुका है। महाराष्ट्र के कई स्थानों के किसानों ने आकर खेती के

गुर सीखे हैं। अब्दुल कलीम अंसारी हर बार की तरह कुछ नया करने वाले ने इस बार अपने खेत में लगभग ढाई एकड़ में एपल बेर का बगीचा लगाया और जिसमें फल आना शुरू हो गए हैं। औसतन 50 से 60 ग्राम की यह एपल बेर मीठी और स्वादिष्ट भी है अपनी महज चार एकड़ कृषि भूमि से लगभग 6 लाख रुपए सालाना आय अर्जित करने वाले कलीम अंसारी के खेत पर उनकी खेती के तौर तरीकों को देखने के लिए कृषि विभाग के कई आला अधिकारी भी आ चुके हैं। वह पूरी तरह जैविक खेती के पक्षधर हैं। फसलों को दी जाने वाली औषधियों को वह जैविक पद्धति से खेत में ही तैयार करते हैं और नाइट्रोजन तैयार करने के लिए वह गाजर घास और गोमूत्र का उपयोग करते हैं। अंसारी ने बताया कि उनके इन प्रयोगों का लाभ भी उन्हें भरपूर मिल रहा है और गेहूं की फसल में 9 इंच तक की बालियां थी जिससे उन्हें गेहूं की फसल का बंपर उत्पादन मिला।

महाराष्ट्र सरकार किसानों को बांटेगी देसी गाय

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र सरकार राज्य के किसानों को देसी गाय बांटेगी। पशुपालन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय के किसानों को दूध देने वाले पशु वितरित किए जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत गाय और भैंस देने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा, अब तक इस योजना के तहत राज्य सरकार विदेश नस्लों की गाय (होल्स्टीन फ्रेजियन और जर्सी) किसानों को देती थी। हालांकि देसी नस्लों की गाय की उपलब्धता बढ़ने के बाद अब इस योजना में इनको भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत जिन नस्लों की गायों को वितरित किया जाएगा, उनमें गिर, साहीवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, देवनी, लाल कंधारी, गौलाओ और डांगी गाय हैं। बता दें कि विदेशी नस्लों के मुकाबले देसी गाय कम मात्रा में दूध देती हैं।

23,000 गांवों में नियुक्त किए जाएंगे पॉवर मैनेजर बिजली से संबंधित शिकायतों और इसकी चोरी से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड 23,000 गांवों में 'पावर मैनेजर' की नियुक्ति करेगी। कंपनी की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति प्रत्येक ग्राम पंचायत में की जाएगी। हाल ही में नागपुर में हुए कार्यक्रम में बिजली मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 'ग्राम विद्युत व्यवस्थापक' का प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। बता दें कि इसका आयोजन बिजली वितरण कंपनी और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास केंद्र ने आयोजित किया था।

120 रुपये प्रति लीटर है इस दूध का भाव

नई दिल्ली (कासं)। पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड ने दिल्ली-एनसीआर में खास दूध पेश किया है। इसका भाव 120 रुपये प्रति लीटर है। यह गाय का प्रीमियम क्वालिटी का दूध है। इस दूध को पुणे की डेयरी से रोजाना हवाई जहाज (एयरलिफ्ट) से दिल्ली लाया जाएगा। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में हर दिन 10 हजार लीटर दूध सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का योजना है। पिछले वित्त वर्ष में 1,950 करोड़ रुपये का टर्नओवर अर्जित करने वाली कंपनी के तीन प्लांट्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में हैं। इनकी कुल क्षमता रोजाना 29 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण करने की है। यह दूध डेयरी फार्म से सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। इस वजह से इसमें किसी तरह की मिलावट संभव नहीं है। इस दूध की एक और खास बात यह है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है. कंपनी के डेयरी फार्म 'भाग्यलक्ष्मी डेयरी' से इस दूध की सप्लाई होगी। इस डेयरी में लगभग 3,000 होलस्टीन फ्रीजियन गाय हैं। यह डेयरी फार्म नवीनतम वैधिक तकनीक से लैस है। कंपनी ने दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश के जिले सोनीपत में फांस की कंपनी डैनोन के एक प्लांट के अधिग्रहण के बाद अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में गाय के दूध की सप्लाई शुरू की थी।

Hindchem Corproation

SUPPER POTASSIUM HUMATE SHINY FLAKES

ZINK EDTA

SEAWEED EXTRACT FLACKES

N.P.K. WATER SOLUBLE FERTILIZER

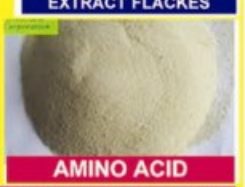
AMINO ACID

- AMINO+HUMIC SHINY BALLS
- FERROUS SULPHATE19%
- MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
- FERROUS EDTA12%
- E.D.T.A. ACID
- CAMPHOR
- SODIUM BICARBONATE
- EDTA DISODIUM
- CITRIC ACID MONOHYDRATE
- MANGANESE SULPHATE 30.5%
- SULPHUR 90% -80WDG
- BORON 20%
- BRONOPOL 25%
- PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

चीनी मिलों की आरएसएफ दर मंजूर

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए राजस्व साझेदारी फॉर्मूला (आरएसएफ) की प्रक्रिया को और आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान में हेराफेरी करने के लिए बिलों में बदलाव को लेकर आ रही शिकायतों की जांच का आदेश भी दिया है। साथ ही 2017-18 के दौरान पेराई करने वाली चीनी मिलों की आरएसएफ दर को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन ने पेराई करने वाली चीनी मिलों की दर राजस्व साझेदारी फॉर्मूला के अनुसार निकालने की प्रक्रिया आसान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गन्ना दर नियंत्रण मंडल की हुई बैठक में राज्य के पेराई सीजन, गन्ना दर आदि के संबंध में चीनी मिलों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि कुछ विषय केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और राज्य सरकार की ओर से उनका अनुपालन किया जाता है। बैठक में 2017-18 के दौरान पेराई करने वाली चीनी मिलों को आरएसएफ गन्ना दर निश्चित की गई और उसे मंजूरी भी दी गई। 181 में से 157 चीनी मिलों की दर आरएसएफ के अनुसार तय की गई है। इनमें से 17 मिलों ने आरएसएफ के तहत एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) से ज्यादा पैसा दिया है। ऐसी 140 मिलों की दर को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है जिनकी आरएसएफ दर एफआरपी से कम है। इस दौरान मुख्य सचिव ने आरएसएफ दर निकालने की प्रक्रिया को और आसान करने का निर्देश भी दिया। मुख्य सचिव ने चीनी मिलों को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ मिलों ने गन्ना कटाई और यातायात खर्च ज्यादा दिखाया है। इसकी जांच की जाएगी। गौरतलब कि किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि कुछ मिलों की तरफ से जो बिल पेश किए जा रहे हैं वे सही नहीं हैं। इस पर जांच का निर्देश दिया गया है। चीनी कारखानों और किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से चीनी की बिक्री दर 34 रुपये तक बढ़ाने की मांग की। चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल 185 चीनी मिलों ने पेराई की है और कुल 426.84 लाख टन गन्ना पेराई की गई है। एफआरपी की कुल रकम 10,487 करोड़ रुपये बैठती है जिसमें से 5,166 करोड़ रुपये की रकम दी गई है। वहीं 174 चीनी मिलों पर 5,320 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। 11 चीनी मिलों ने 100 फीसदी एफआरपी दिया है। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव यूपी एस मदान, सहकारी विभाग की प्रधान सचिव आभा शुक्ला, चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ समेत चीनी मिलों एवं किसानों के प्रतिनिधि और समिति सदस्य उपस्थित थे।

फसलों का दुश्मन कीट फॉल वॉलवर्म

रायपुर (विसं)। पिछले 12 सालों से अमेरिका की सौ से अधिक प्रजाति की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा फॉल वॉल वर्म कर्नाटक के रास्ते अब छत्तीसगढ़ में दाखिल हो गया है। बस्तर जिले के तोकपाल, बकाखंड और बस्तर ब्लॉक के खेतों में ये कीट कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हारावंड के वैज्ञानिकों को दिखाई दिए है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र रायपुर के अधिकारियों के साथ कीट प्रभावित ब्लॉक के गांव का निरीक्षण है। बस्तर ब्लॉक के बड़ेचकवा में मक्का की फसल पर इस कीट का संक्रमण पाया जाता है।

यह कीट पिछले एक दशक में अमेरिका और अफ्रीकी देशों में भारी तबाही मचा चुका है। भारत में इस तरह के कीट की पुष्टि हाल ही में हुई है। यह फिलहाल देश के कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया गया है। इस नये कीट पर वैज्ञानिकों ने शोध किया गया है। उनके मुताबिक यह 180 प्रकार की फसलों को चट कर जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जिन खेतों में फॉल वर्मी कीट पाया गया है उनमें मक्के की फसल ली जा रही है। आने वाले दिनों में कीट का प्रकोप धान और गन्ने की फसल पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही यह कीट गोभी, टमाटर, कपास आदि की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात को पाया है कि कीट का आक्रमण मक्के की फसल पर शुरू की अवस्था में ही दिख जाता है। कीट की झल्लियां फसल के पत्तों को खुरचकर खाना शुरू कर देती है।

यह कीट इतना खतरनाक है कि एक बार अगर किसी फसलों में लग जाए तो उसके साथ अंडे और लार्वा अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक लेकर लगा रहता है। यह फसल को एक से तीन माह के अंदर पूरी तरह से खाकर नष्ट कर देता है।

अब कर्जमाफी के बाद किसानों को ताम्रपत्र देगी सरकार

भोपाल (विसं)। अब मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों को स्व तंत्रता सेनानियों की भाँती ताम्रपत्र देने का फैसला लिया है। ये ताम्रपत्र किसानों को कर्जमाफी के बाद सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। ये तांबे के पत्र जिन किसानों को दिये जायेगें, उस पर सरकार द्वारा माफ़ किया कर्ज का पूरा लेखा-जोखा होगा, जैसे- बैंक और समिति का नाम, कर्ज और माफी की गई पूरी राशि आदि। यह एक प्रकार से सरकार द्वारा माफ किये गए कर्ज का प्रमाण पत्र होगा। माना जा रहा है की कांग्रेस कर्जमाफी के मुद्दे को लोकसभा चुनाव 2019 में भुनाने वाली है। इसी कर्जमाफी के मुद्दे की बदौलत कांग्रेस मध्यप्रदेश में 15 साल का वनवास काट कर सत्ता में वापस आई है। अब इसी मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी में है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक प्रदेश में कर्जमाफी की प्रक्रिया चालू कर दी है। अब तक की बात करें तो प्रदेश में 53 लाख 18 हजार 757 किसानों के खातों में 42 लाख 4 हजार 463 रुपए ऋण माफी के लिए आवेदन दिए है। जिसमे से 14 लाख 29 हजार 879 किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। शेष बचे हुए किसानो के खातों में जल्द पैसे भेज दिये जाएंगे। इस कर्जमाफी (जय किसान फसल ऋण योजना) के बाद सरकार किसानों को ताम्रपत्र देगी जो एक तरिके से कर्जमाफी का प्रमाण होगा। हालाँकि अभी ये तय नहीं है की ताम्रपत्र से कैसा होगा। मीडिया में खबरें आ रही है की अभी इसके सैंपल मगवाये गए है जल्द ही इसे फाइनल कर छापने के आदेश दे दिए जायेंगे. इसके पीछे कांग्रेस सरकार का मकसद है किसान इस कर्जमाफी को हमेसा याद रखे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकतंत्र सेनानीयों को ताम्रपत्र बाटे थे जो स्वतंत्रता सेनानियों को दिए गए थे। जिला कलेक्टरों के माध्यम से वितरित किया गया था।

अंगूर की बेहतरीन खेती करने वाले किसानों का सम्मान

नासिक (विसं)। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सहायक कंपनी महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हाल में नासिक में अंगूर के निर्यात में बेहतरीन उत्पादकता और गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने की मिसाल कायम करने वाले 11 किसानों को सम्मानित किया है। इन किसानों ने अपने प्रयासों से यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि महिंद्रा के उत्पाद यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम के कड़े खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले हों। इन किसानों ने कनाडा, मलेशिया और चीन जैसे नए बाजारों में उच्चतम गुणवत्ता वाले मानक अंगूर की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए विदेशी देशों में भारत की गुडविल और ब्रांड छवि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। समारोह में लगभग 1,200 किसान, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ अपने लंबे जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए और सम्मानित होने वाले अपने उन किसान भाइयों के लिए तालियां बजाईं, जिन्होंने यूरोपीय संघ के गंतव्यों में उच्च मात्रा के निर्यात के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में भी उच्च स्तर हासिल किया है। महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ अशोक शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, 'एमएएसएल के अंतर्गत हम महाराष्ट्र में लगभग 1,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं जो खेती में उत्पादकता और अंगूर की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित हैं।

बारिश से लहलहाई गेहूं की फसल

लखनऊ (विसं)। ठंड के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में हुई बारिश ने जहां ठंडक बढ़ा दी है, वहीं किसान खुशी से झूम उठे हैं। रबी की फसलों के लिए अमृत मानी जा रही इस बारिश ने गेहूं की कमजोर हो रही फसल को जीवनदान दिया है। बाकी फसलों के लिए भी यह बारिश मुफीद साबित हो रही है। इस साल कोहरा कम पड़ने से रबी की फसल को नुकसान हुआ है।

31 महीने के ऊपरी स्तर पर सोयाबीन

नई दिल्ली (विसं)। वैश्विक बाजार में दाम बढ़ने और कारोबारियों की तरफ से बड़ी मांग के कारण सोयाबीन के दाम करीब छह साल के ऊपर स्तर पर पहुंच गए। घरेलू स्तर पर चुनावी साल में किसानों की उपज का बेहतर मूल्य घोषित होने की संभावना और वैश्विक स्तर पर चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध में सुलह की बढ़ती संभावनाओं की वजह से सोयाबीन मजबूती की राह पर है। देश में उत्पादन अधिक होने के बावजूद वैश्विक मांग के कारण सोयाबीन के दाम नया रिकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वायदा बाजार में सोयाबीन के दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गए जबकि हाजिर बाजार में 3,900 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गए, जो पिछले करीब 31 महीने का उच्चतम स्तर है। इसके पहले 15 जून 2016 को सोयाबीन के दाम 3,964 रुपये प्रति क्विंटल पर थे। एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन फरवरी अनुबंध 3,909 रुपये, मार्च 3,953 रुपये, अप्रैल 3,985 रुपये, मई 4,023 रुपये और जून अनुबंध की कीमतें बढ़कर 4,050 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं। सोयाबीन में तेजी आने की कई वजह हैं।

यूपी में अब निजी क्षेत्र भी स्थापित कर सकेगा मंडियां

लखनऊ (विसं)। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र की मंडियां खुलने की राह आसान हो गई है। इसके लिए योगी सरकार ने मंडी अधिनियम 1965 में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद सहकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र भी मंडियों की स्थापना कर किसानों के उत्पाद सीधे खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर निजी क्षेत्र की मंडियों की स्थापना के लिए जमीन देने का प्रस्ताव किया है। निजी क्षेत्र की मंडियां खुलने से किसानों को अपने उत्पादों का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकेगा। साथ ही सहकारी मंडियों को इनसे मुकाबला करना होगा।

योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इससे निजी मंडियों में नई तकनीकी के साथ ही कृषि विपणन में बड़े पैमाने पर निजी निवेश हो सकेगा। निजी क्षेत्र की मंडियों में अपने उत्पाद बेचने व खरीदने वालों को सरकार अन्य सुविधाएं देगी। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों व मंडियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे निजी मंडियों के लिए जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। गोरखपुर से आजमगढ़ को जोड़ने वाली इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.35 किलोमीटर होगी जबकि इस पर 5,555 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने पर 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा चित्रकूट से होकर इटावा तक बनने वाली 297 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे भी निजी मंडियां खुलेंगी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए इस तरह का प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर सरकार ने सहकारी क्षेत्र की मंडी का निर्माण कराया है।

फरवरी महीने में होने वाले खेती बाड़ी के कार्य

फरवरी माह जिसे आप माघ-फाल्गुन भी कहते हैं , बसंत पंचमी का त्यौहार लेकर आता है ।

फरवरी माह के कृषि कार्य

चारों तरफ पीले फूल खिल उठते हैं तथा मौसम में ठंड कम होने लगती है। इस माह के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं-

❖जनवरी में उगाई गई सब्जियों के पौधों की रोपाई की जाती है। खेतों में भिण्डी, तोरई, कद्दू, लौकी, चौलाई और मूली के बीजों को बोते हैं और इन सबकी सिंचाई की जाती है।

❖बौने गेहूं में उर्वरक की आखरी मात्रा देकर सिंचाई करते हैं।

❖सूर्यमुखी के खेत में निदाई करते हैं और मिट्टी चढ़ाई जाती है।

❖गन्ने के स्वस्थ बीज का चुनाव कर बीजोपचार करते हैं।

❖बरसीम की कटाई 20 से 25 दिनों के अन्तर में की जाती है।

❖बरसीम, चटी के लिये मक्का, ज्वार, लोबिया और मक्का मिलाकर बोते हैं।

❖सरसों, अलसी यदि पकने लगे हों तो उन्हें काट लिया जाता है। नहीं तो ज्यादा पक जायेगा और बीज छिटकने लगेंगे।

❖प्याज और लहसुन के खेतों में गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं।

❖आलू की खुदाई करते हैं। जाड़े के फूलों के बीज एकत्र करते हैं। गर्मियों के फलों के बीजों की बुवाई करते हैं।

कृषि कार्य में ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें

पैदावार में कमी

फरवरी माह में यह रोग बहुत सारी फसलों में हमला करता है तथा पत्तियों पर सफेद चूर्ण नजर आता है । इसकी तुरंत रोकथाम के लिए 1 कि.ग्रा. घुलशील गंधक का छिडकाव करें।

दीमक प्रकोप (बारानी क्षेत्रों में): इस माह बारानी व रेतीली क्षेत्रों में दीमक बहुत सी फसलों पर हमला करके नुकसान करती है। नियंत्रण के लिए 2 लीटर क्लोरपाइरीफास को 2 लीटर पानी तथा 20 कि.ग्रा. रेत में मिलाकर खेत में बिखेर दें।

चेपा व तेला कीट (प्रमुख फसल नाशक): इस माह चेपा व तेला दोनों कीट बहुत सारी फसलों की पत्तियों, फूलों, फलों व बालियों से रस चूसकर पैदावार कम करता है । यदि 12 प्रतिशत से अधिक पत्तों पर ये कीट नजर आयें तो 400 मि.ली. मैलाथियान 70 ईसी को 270 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें।

गेहूं : गेहूं में सिंचाई 27-30 दिन के अन्तर पर करते रहें । इस माह तापमान बढ़ने के दशा में गेहूं में बीमारिया नजर आने लगती है जिनमें पीला रतुआ या धारीदार रतुआ, भूरा रतुआ या पत्तों का रतुआ तथा काला या तने का रतुआ रोग प्रमुख है। इन रोगों के रंगदार धब्बे पत्तों व तनों पर नजर आते हैं। बीमारी नजर आते ही 800 ग्राम जिनेब (डाईथेन जेड 78) या मैनकोजेब (डाईथेन एम-45) को 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें । उसके बाद 10-17 दिन के अन्तर पर 2 या 3 छिड़काव करें । चूर्णी या पाउडरी मिल्ड्यु बीमारी में पत्तों में सफेद चूर्ण बन जाता है। जिससे बाद में बालियां भी रोगग्रस्त हो जाती है । रोग नियंत्रण के लिए 800-1000 ग्राम घुलनशील गंधक का छिड़काव करें। रोगरोधी किस्में लगाना ही सर्वोत्तम बचाव है। बाकी कीट व अन्य बीमारियों का नियंत्रण के लिए पिछले माह के लेख देखें ।

जौ एवं शरदकालीन मक्का : जौ एवं शरदकालीन मक्का में आवश्यकतानुसार सिंचाई कर सकते है। जौ में बीमारियों का नियंत्रण गेहूं की भाति ही करें। शरदकालीन मक्का में यदि रतुआ तथा चारकोल बंट का खतरा होने पर 400-600 ग्राम डाइथेन एम 47 को 200-250 लीटर पानी में घोलकर 2-3 छिड़काव करें ।

चना : यदि भारी मिट्टी में उगाया है तो ज्यादा

सिंचाई न दें। चने में बीमारियों से बचाव के लिए सहनशील किस्में चुनें, बैविस्टीन से बीजोपरचार (2.7 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज) करें तथा समय पर बोआई करें। रोगग्रस्त पौधों को जलाकर नष्ट कर दें।

मसूर, दाना मटर व चने में फलीछेदक के नियंत्रण के लिए फूल आते ही 400 मि.ली. एण्डोसल्फान 37 ई सी 100 लीटर पानी में मिलाकर छिडकाव करें तथा 510 प्रतिशत फत्रियां बळनत्रे पर छिडकाव फिर दोहराएं ।

भूरी सरसों, तारामीरा व अगेती पीली सरसों इस माह पकने वाली है तथा माह के शुरू में हल्की सिंचाई देने से पैदावार बढ़ेगी। कीट नियंत्रण के लिए पिछले माह बताये तरीकों पर ध्यान दें। फलियां पीली पड़ने पर फसल काट लें इससे दाने बिखरते नहीं। फसल काट कर एक स्थान पर ढेर लगाकर सुखाएं तथा अच्छी तरह सुखने पर गहाई करें ।

चारा: चारा जैसे बरसीम, रिजका व जई की हर कटाई के बाद सिंचाई करें इससे अगली कटाई जल्दी मिलेगी।

सूरजमुखी: सूरजमुखी की फसल 17 फरवरी तक लगाई जा सकती है। पक्षी बीजों को निकाल कर ले जाते है इनसे बचाव के लिए ध्वनि करें। बाकी क्रियाएं पिछले माह बता चुके है। दिसम्बर व जनवरी में बोयी फसल में 30-37 दिन बाद पहली सिंचाई कर दें तथा नेत्रजन की दूसरी किस्त (1 बोरा यूरिया) भी डाल दें ।

बसंतकालीन गन्ना: बसंतकालीन गन्ना को 17 फरवरी से मार्च अनन्त तक बोया जा सकता है। 35,000 दो आखों वाली या 23,000 तीन आखों वाली (35-40 किंवटल) पोरियों को 0.25 प्रतिशत डाईथेन एम 45 के 100 लीटर घोल में 4-7 मिनट तक डुबोकर 2 से 2.7 फुट दूर लाईनों में बोएं। बीज के लिए गन्ने के ऊपरी दो तिहाई स्वस्थ्य, कीट व रोगरहित हिस्से को चुने। उपचार करते समय रबर के दस्ताने पहनें तथा काम करने वाले व्यक्ति के हाथ पर घाव या खरोंचें न हो। यदि क्षेत्र में स्केल कोड़े का डर है तो बीज को 0.1 प्रतिशत मैलाथियान के घोल में 20 मिनट तक भिगों लें तथा गन्ने की मोठी फसल न लें । अगेती पकने वाली किस्मों में सी ओ जो 64, 18-20 प्रतिशत खांड तथा 200 क्विंटल पैदावार देती है तथा मोठी फसल भी अच्छी देती हैं। सी ओ एच 76 तथा सी ओ एच 92 भी 18 प्रतिशत खांड देती हैं। मध्यम पकने वाली किस्मों में सी ओ 7717 नवम्बर में पक जाती है तथा 17 प्रतिशत खांड तथा 370 क्विंटल पैदावार देती हैं। सी ओ एच 99 तथा सी ओ एच 8436 भी 17 प्रतिशत खांड तथा 280 क्विंटल पैदावार देते हैं । पिछेती पकने वाली किस्मों में सी ओ 1148 जनवरी अंत में पकती है तथा 17-19 प्रतिशत खांड के साथ 320 क्विंटल पैदावार देती है ।

सी ओ एस 351, 18-20 प्रतिशत खांड तथा 320 क्विंटल पैदावार देती है। सी ओ एस 767, दिसम्बर माह में पकती है तथा 16-18 प्रतिशत खांड के साथ 300 क्विंटल पैदावार देती हैं। बीजाई से पहले खाद, मिट्टी परीक्षण के आधार पर डालें । यदि मिट्टी जांच नहीं हुई है तो 2.7 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरा यूरिया (1/3 नेत्र जन) डाल दें । गन्ने में 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट भी डालें, विशेषकर बलुई-दोमट भूमि में। बीजाई के बाद नमी बचाने के लिए भारी सुहागा लगाएं। दोपहर को बीजाई न करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 1.6 कि.ग्रा. सीमाजीन - 70 घुलनशील पाउडर 270 लीटर पानी में मिलाकर बीजाई के 2-3 दिन बाद छिडकें । बीजाई के 10-17 दिन बाद अंधी गुड़ाई करके सुहागा लगा दें इससे खरपतवार नियंत्रण में रहेगें । गळ्याने की शरदकालीन फसल में 30 दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहें तथा घास फूस निकालते रहें । यदि मोथा की समस्या ज्यादा हो तो 2, 4-डी इस्टर का 400 ग्राम, 300 लीटर पानी में छिड़काव करें । इस फसल में फरवरी-मार्च माह में दीमक, कनसुआ व जडवेधक का आक्रमण से बचाव करने के लिए 2.5 लीटर क्लोरपाइरीफास 20 ई सी या 1.5 लीटर एण्डोसल्फान 35 ई सी का 6001000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

वानिकी: पोपलर का पेड गहरी उपजाऊ अच्छे जल निकाल वाली भूमि में अच्छा होता है । इसे फरवरी माह में कलमों द्वारा 2×2 फुट दूरी पर नर्सरी में लगाया जा सकता है तथा अगले वर्ष पौधों को जनवरी फरवरी में खेत में लगा सकते हैं । नर्सरी में कलमें लगाने से पहले कैप्टान या डायथैन (0.3 प्रतिशत) घोल में डुबोए ताकि बीमारियों से बचाव रहे । पौधों को 3 फुट गहरे गड्ढे खोदकर ऊपर की आधी मिट्टी में गोबर की सड़ी-गली खाद मिलाकर भरें तथा पूरा पानी लगाएं। पौधों को मेढों पर कतारों में 10 फुट दूरी पर तथा सिंचाई नाली के दोनों ओर कतारों में 7 फुट दूरी पर लगाएं। यदि खेत में अकेले पापुलर लगाना हो तो 16×16 फुट दूरी रखें इससे 270 पौधों लग जाएगें। पौधे लगाने से पहले 1 एकड़ में 1 लीटर क्लोरपाइरीफास पानी के साथ दें । इससे टीमक पर नियंत्रण रहेगा । हर महिने सिंचाई करें ।

मुलेठी: एक बहुवर्षीय औषध फसल है । यह खांसी दूर करने की दवाई बनाने के काम आती है । इस फसल को फरवरी-मार्च या फिर जुलाई-अगस्त में लगाया जा सकता है। हरियाणा मुलेठी नं.1 पकने में 2.7 से 3 वर्ष लेती है तथा 30 किंवटन सूखी जड़ों की पैदावार देती है। बीजाई / रोपाई के लिए 170 कि.ग्रा. 6 ईंच लम्बी 3-4 आखों वाली स्वस्थ्य जड़ों को 3 फुट दूरी पर 3/4 जड़ के हिस्से का जमीन में दबा दें । पौधों में आपसी दूरी 1.7 फुट रखें। खेत तैयारी के समय 17-20 गाड़ी गोबर की सड़ी गली खाद के साथ 1 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट, आधा बोरा यूरिया डालें बाकी आधा बोरा यूरिया फुटाव के 1 महिने बाद डालें। अच्छी फसल के लिए वर्ष में 7-6 सिंचाईयां करें। प्रति वर्ष जनवरी माह में जमीन से ऊपरी भाग को काट दें ताकि फुटाव अच्छा हो तथा फसल को प्रतिवर्ष मार्च में 3/4 बोरा यूरिया सिंचाई के साथ दें । फसल लगने के 2.7 - 3 वर्ष बाद 1.7 - 2 फुट गहरी खुदाई करके जड़े निकाल दें ।

फल: जैसे कि अंगूर, आड़ू, आलुचा, अनार, नाशपाती आदि फरवरी में लगा सकते हैं । अंगूर की किस्में खाने के लिए बिना बीज की ब्यूटी सीडलैस, डिलाइट , परलेट व थोम्पसन सीडलैस तथा बीज वाली बैकुआ; आवाद, चैम्पियन अर्ली, मस्केट, गोल्ड व कार्डिनल हैं। किसमिस बनाने के लिए थोम्पसन सीडलैस व गोल्ड; डिब्बाबंद के लिए थोम्पसन सीडलैस तथा शर्बत बनाने के लिए ब्यूटी सीडलैस, अर्लो मस्केट व चैम्पियन किस्में हैं । नीबू जाति के पौधे में सुण्डी छाल खाने तथा तनों में छेद करती हैं। इन छेदों में 30 मि.ली. इण्डोसल्फान 35 ई सी को 10 लीटर पानी में घोलकर डालें यदि तळेने या फल गल रहे हों तो जनवरी के उपचार बाद फरवरी में स्ट्रेप्टासाइक्लिन का स्प्रे करें। नीबूं जाति के फलों तथा आम व लीची फरवरी में खाद व सिंचाई पौधों की आयु के हिसाब से दें। तरबूज की फसल में फरवरी में लग सकती है जिसके लिए 3 कि.ग्रा. बीज को 2.7-3 फुट दूरी पर 2 फुट दूरी बनी मेढ़ों के सिरे पर लगाएं। बीजाई से पूर्व बीज को 1 ग्राम बाविस्टीन में 1 लीटर पानी में 10-15 घंटे तक भिगोएं तथा गर्म जगह पर अंकुरित कर लें । खेत में 10 टन गोबर की खाद, 2 बोरे यूरिया, 2 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट व 1 बोरा म्युरेट आफ पोटाश बीजाई पर डालें। असाई यामाटों व सुगर बेबी किस्में 100-120 किंवटल पैदावार देती हैं ।

खरबूज के लिए 2.7 ग्राम बीज को 2 -2.7 फुट दूरी पर मेढ़ों पर लगाएं । बाकी क्रियाएं तरबूज की तरह ही हैं । किस्मों में पूसा शरबती, पूसा मधुरस तथा पूसा रसराज 77-100 क्विंटल पैदावार दे देती है ।

सब्जियां: फरवरी माह में बंसत ऋतु की निम्नलिखित सब्जियां लग सकती हैं ।

घीया की पूसा समर परोलीफिक लोग व राऊड, पूसा नवीन, पूसा मंजरी व पूसा मेघदूत किस्में लगाएं (बीज मात्रा 2 कि.ग्रा. दूरी 2×10 फुट)।

कद्दू की पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड किस्में हैं (बीज मात्रा 2.7 कि.ग्रा.दूरी 2 × 10 फुट)।

करेला की पूसा दो फसली तथा पूसा विशेष किस्में हैं (बीज मात्रा 2.7 कि.ग्रा. दूरी 1 × 6 फुट) खीरा - जापानी लॉग ग्रीन, स्ट्रेटऐट, पूसा सनयोग किस्में हैं (बीज मात्रा 1 कि.ग्रा. दूरी 3×7 फुट) ।

तोरी पूसा सुप्रिया व पूसा रसदार किस्में हैं (बीज मात्रा 2 कि.ग्रा., दूरी 3 × 10 फुट) । यह सभी बेलदार फसलें हैं तथा नालिया बनाकर इन्हें नाली के ऊपर मेढ़ों के किनारों पर लगाएं । नालियां सिंचाई के काम आती हैं । बीजाई के समय 10 टन गोबर की गली-सडी खाद, 1 बोरा यूरिया, 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट तथा आधा बोरा म्युरेट आफ पोटाश डालें । जब फसल पर 8-10 पत्ते निकल आएं तो आधा बोरा यूरिया डालें ।

भिन्डी को भी फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च तक बो सकते हैं । 8 कि.ग्रा. बीज को बोने से पहले 12 घंटे 0.07 प्रतिशत बाविस्टीन घोल में भिगोए फिर 1 फुट कतारों में 6 ईंच की दूरी पर बोयें । खेत की तैयारी के समय 10 टन गोबर की सड़ी-गली खाद के साथ आधा बोरा यूरिया 1.7 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट तथा आधा बोरा म्युरेट आफ पोटाश डालें। उन्नत किस्में पूसा ए-4, पूसा मखमली, पूसा सावनी तथा परकिन लोंग ग्रीन हैं ।

बैंगन व टमाटर की रोपाई भी फरवरी शुरू में की जा सकती हैं । जिसके लिए नर्सरी नवम्बर में बोई गई थी ।

फूल: सर्दियों के फूल पूरी बहार पर होंगे । फूलों में देशी खाद व पानी लगाएं। फरवरी अंत तक गर्मी के फूलों की नर्सरी की बीजाई कर लें।

फरवरी-मार्च में करें इन 10 सब्जियों की बुवाई, होगा अच्छा मुनाफा

इस मौसम में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पेठा, पालक, फूलगोभी, बैंगन, भिण्डी, अरबी जैसी सब्जियों की बुवाई करनी चाहिए।

खीरा : खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुवाई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुवाई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई-गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें।

ककड़ी :ककड़ी की बुवाई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए एक एकड़ भूमि में एक किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की तीन से चार बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए।

करेला : हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुवाई दो तरीके से की जाती है - बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है।

लौकी : लौकी की खेती कर तरह की मिट्टी में हो जाती है लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांध कर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए।

भिंडी भिंडी की अगेती किस्म की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को दो-तीन बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सेमी और कतार में पौधे की बीच की दूरी 15-20 सेमी रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद निराई-गुड़ाई करना जरुरी रहता है।

तोरई : हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुवाई से पहले, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके बाद 2 से 3 बार बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत कि तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में न लगाएं इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है।

पालक : पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है लेकिन ध्यान रहे अम्लीय जमीन में पालक की खेती नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब वह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना चाहिए, इसके बाद 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए।

अरबी : अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए। जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेमी. व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए। इसकी गांठें को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें।

बैंगन : इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुवाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर का खाद बिखेर दे। बैंगन की खेती के लिए दो पौधों और दो कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए।

पेठा : पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सब से अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुवाई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर के मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर के पाटा लगाना चाहिए।

आम के स्वाद वाली अदरक की ये प्रजाति है बहुत खास

लखनऊ (विसं)। इस पौधे की पत्तियां हल्दी के पौधे की तरह होती हैं, लेकिन स्वाद बिल्कुल कच्चे आम जैसा, और इसकी गांठे अदरक तरह होती है। देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाने जाना वाला ये अदरक की प्रजाति का पौधा होता है। अदरक की ये किस्म बहुत खास होती है, जो भी देखता है उसे यही लगता है कि ये हल्दी ही है। ये औषधीय पौधा होता है कई तरह की रोगों में काम आता है। अभी कच्चे अदरक की चटनी में बिल्कुल कच्चे आम का स्वाद आता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमालय, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। गर्मियों में इसमें गुलाबी, बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं तो लोग इसे बगीचे में भी लगाते हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. विक्रमा प्रसाद पांडेय बताते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्यूरकुमा अमाडा होता है, इसमें कच्चे आम की महक आती है, इसे आमा हल्दी भी कहा जाता है, अलग-अलग प्रदेशों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। इसका प्रयोग कई तरह के रोगों के उपचार में होता है। विश्वविद्यालय की तरफ से प्रयोग के तौर पर कई किसानों को मैंगो जिंजर के गांठे दी गई थी, कई किसानों के यहां अच्छा उत्पादन भी हुआ है।

अदरक की प्रजाति को मराठी में अंबे हल्दी, हिंदी में आमा हल्दी और इंग्लिश में मैंगो जिंजर कहा जाता है।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

कीट हमले से घट सकता है चीनी उत्पादन

सुरेश शर्मा

मुंबई। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में गन्ने की फसल पर कीट हमले की खबरों के बावजूद इस साल राज्य में चीनी उत्पादन में सिर्फ 0.5 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है। प्रमुख चीनी संगठन अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने महाराष्ट्र में मौजूदा पेराई सत्र 2018-19 के लिए चीनी उत्पादन 1.01 करोड़ टन पर रहने का अनुमान जताया जबकि पिछले सीजन के दौरान यह 1.07 करोड़ टन था। महाराष्ट्र इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 1.16 करोड़ टन के अनुमानित उत्पाद के बाद देश में दूसरा प्रमुख चीनी उत्पादक है। एक सप्ताह पहले उद्योग संगठन भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने महाराष्ट्र में 95 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जताया था। एआईएसटीए के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी ने कहा, 'महाराष्ट्र की मिलों से 1.01 करोड़ टन के योगदान के साथ हमने इस सीजन मे भारत का कुल चीनी उत्पादन 3.15 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है।' एआईएसटी का राष्ट्रीय चीनी उत्पादन अनुमान इस्मा द्वारा जताए गए 3.07 करोड़ टन के अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत 29 रुपये पर निर्धारित किए जाने के साथ सरकार ने मिलों को 1,000 रुपये प्रति टन की ढुलाई सब्सिडी और गन्ना किसानों को 138 रुपये प्रति टन का इंसेंटिव दिए जाने की भी पेशकश की है। इससे सरकार पर 5,538 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वहीं सरकार ने मिनीमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा (एमआईईक्यू) के तहत चालू वर्ष के दौरान 50 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। इस्मा ने कहा है, 'चीनी निर्यात के रुझान को देखते हुए माना जा रहा है कि चीनी मिलें 50 लाख टन के आवंटित एमआईईक्यू की तुलना में 2018-19 में लगभग 30-35 लाख टन चीनी के निर्यात में सक्षम हो सकती हैं।'

'बकाया नहीं देने वाली मिलों पर कार्रवाई जल्द'

मुंबई (कार्स)। गन्ना आयुक्त की ओर से बकाया भुगतान में चूक करने वाली चीनी मिलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद करीब 8,000 किसानों ने दिन भर चला विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर ये किसान स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के बैनर तले सांसद राजू शेट्टी की अगुआई में गन्ना आयुक्त कार्यालय के सामने जमा हुए। गन्ना आयुक्त की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन छिटपुट हिंसा के साथ समाप्त हो गया। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के प्रवक्ता योगेश पांडे ने कहा, विभिन्न 170 परिचालित मिलों में से 39 चीनी मिलें राज्य भर में फैली हुई हैं। इन चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर, 2018 को शुरू हुए मौजूदा पेराई सीजन के बाद से एक पैसा का भी भुगतान नहीं किया है। हालांकि इन मिलों ने किसानों से कई टन गन्ना खरीदा है। असल में परिचालन करने वाली कई मिलों ने 20-30 फीसदी गन्ना बकाये का ही भुगतान किया है। ये मिलें सरकार से नए चीनी पैकेज की उम्मीद कर रहीं हैं जिसके चलते वे गन्ने का भुगतान रोक रही हैं। गन्ना आयुक्त द्वारा ऐसी मिलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद हमने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल गन्ना बकाया 5,600 करोड़ रुपये बैठता है जबकि राज्य में चीनी के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के एक बड़े हिस्से का अग्रिम भुगतान सीधे किसानों को करने की नीति है।

ई-नामः किसानों के लिए ऑनलाइन मंडी से अब इंटरस्टेट ट्रेडिंग

नई दिल्ली (विसं)। देश की महत्वाकांक्षी ई-नाम (देशभर में अग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल) ने इस महीने चार राज्यों के किसानों के साथ एक नई शुरुआत कर दी है। मंडियों या राज्यों से अलग, ये किसान पहली बार अपने फसलों के लिए इंटर-स्टेट ट्रेडिंग के जरिए बेस्ट प्राइस पा सकेंगे। हालांकि, एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस बैरियर को पार करने में करीब 3 साल लग गए। बता दें कि अप्रैल, 2016 में फार्म कमोडिटिज़ के लिए एक यूनिफाइड नैशनल मार्केट बनाने के लिए इस ई-प्लैटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। इंटर-स्टेट ट्रेडिंग इस प्लैटफॉर्म का एक अहम पहलू था। देश में सबसे पहले इंटर-स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली और उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसानों के बीच टमाटर की ट्रेडिंग रिकॉर्ड हुई। इसी तरह, तेलंगाना में गद्वाल मंडी और आंध्र प्रदेश के कुरनूल के किसानों के बीच 19 जनवरी को मूंगफली का व्यापार हुआ। तेलंगाना सरकार के अग्रीकल्चरल मार्केटिंग निदेशक लक्ष्मी बाई ने कहा, यह बहुत उत्साहवर्धक है। हमने इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग की जिम्मेदारी लेने के लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के लिए एक नया लाइसेंस पेश किया है। उन्होंने बताया कि एक राज्य के किसानों के कृषि उत्पादों की मांग किसी दूसरे राज्यों में ज्यादा होती है, तो यह ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन कीमतों को ध्यान में रखने के बावजूद उनके लिए फायदेमंद होगी। इंटर-स्टेट ट्रेडिंग में लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, एजेंट दूर बैठे ग्राहक के हिसाब से स्टोरेज, क्वॉलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी लेंगे।

इस नए कदम के साथ ही देश में अग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अभी 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के कॉमन ई-मार्केट प्लैटफॉर्म पर 585 मंडियों में 124 फार्म कमोडिटिज़ में इस तरह की ट्रेडिंग संभव है।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर
1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर
1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

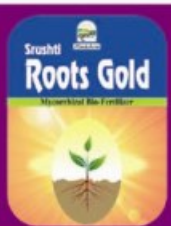

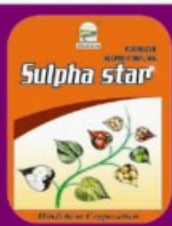

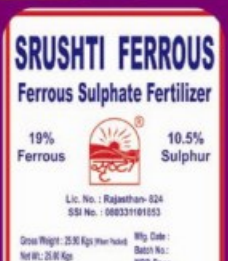

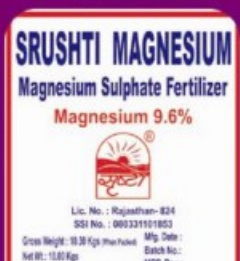

FERTILIZER
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS
- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425